साान्ध्य हिन्दी दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 03 | अंक - 76 | जौनपुर, बुधवार, 06 नवम्बर 2024 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज - 4 | मूल्य - 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

अमानतुल्ला खान को नहीं मिली राहत, बढ़ी न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली, एजेसी। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने ईडी द्वारा दायर एक आवेदन पर खान की हिरासत बढ़ा दी, जिसमें दावा किया गया था कि मामले की जांच महत्वपूर्ण चरण में है और अगर रिहा किया गया, तो खान जांच में बाधा डाल सकता है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। न्यायाधीश 6 नवंबर को यह फैसला कर सकते हैं कि मामले में खान के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। ईडी ने 29 अक्टूबर को 110 पेज का पहला पूरक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि खान ने कथित तौर पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के माध्यम से उत्पन्न धन का शोधन किया। आरोपपत्र में मरियम सिद्दीकी का नाम है, जिसे ईडी ने मामले में आरोपी के रूप में गिरफ्तार नहीं किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आगे दावा किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में खान और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत थे। खान की जमानत याचिका पर 7 नवंबर को सुनवाई होने की संभावना है। ईडी ने दिल्ली के ओखला इलाके में उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद 2 सितंबर को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत खान को गिरफ्तार किया था और दावा किया था कि जब उनसे पूछताछ की गई तो वह ष्टाल–मोलष कर रहे थे। खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच दो एफआईआर से जुड़ी है– वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो का मामला और दिल्ली द्वारा दर्ज कथित आय से अधिक संपत्ति का मामला।

दिल्ली में 400 तक पहुंच गया प्रदूषण का स्तर

नई दिल्ली, एजेसी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली में बुधवार से लोगों को खुले में कचरा जलाने से रोकने का अभियान शुरू होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में खुले में कचरा जलाने की घटनाओं की सूचना देने के लिए नागरिक एजेंसियों की 588 टीम तैनात की जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 400 तक पहुंच गया है, अगले 10 दिन महत्वपूर्ण होंगे। गोपाल राय ने आज राष्ट्रीय राज धानी में बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली में मंगलवार को भी प्रदूषण का स्तर अधिक रहा और कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी के करीब पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एक्यूआई) के आंकड़े के अनुसार, सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 384 दर्ज किया गया। सोमवार को शाम चार बजे तक दर्ज पिछले 24 घंटे का औसत एक्यूआई 381 था, जो देश में दूसरा सबसे अधिक एक्यूआई है। हर घंटे वायु गुणवत्ता की जानकारी देने वाले सीपीसीबी के 'समीर ऐप' के अनुसार, 38 निगरानी केंद्रों में से 13 में एक्यूआई 400 से अधिक यानी 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया। ये केंद्र हैं आनंद विहार, अशोक विहार, द्वारका, एनएसआईटी द्वारका, नेहरू नगर, मोती मार्ग, सोनिया विहार, विवेक विहार, वजीरपुर, रोहिणी, पंजाबी बाग, मुंडका और जहांगीरपुरी।

भारत औपनिवेशिक विचारों को नकार रहा है - उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत तेजी से औपनिवेशिक मानसिकता को छोड़ रहा है। हम अब पूर्व में पूजनीय औपनिवेशिक विचारों और प्रतीकों को चुनौती दे रहे हैं। भारतीय लोक प्रशासन में भारतीय विशेषताएं होनी चाहिए, जो औपनिवेशिक मानसिकता से दूर हों, जो स्वतंत्रता के बाद हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप हो। यह बातें उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़ ने कही। वह नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की 70वीं वार्षिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। भारतीय लोक प्रशासन में भारतीय विशेषताएं होनी चाहिए जो औपनिवेशिक मानसिकता से परे हो और स्वतंत्रता के बाद की हमारी

आकांक्षाओं के अनुरूप हों। भारत तेज गति से औपनिवेशिक मानसिकता को छोड़ रहा है। अब चिकित्सा या प्रौद्योगिकी सीखने के लिए अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं है। देश आज औपनिवेशिक विचारों और प्रतीकों को चुनौती दे रहा है। राजपथ अब कर्तव्य पथ है और रेस कोर्स रोड अब लोक कल्याण मार्ग है। नेताजी अब उस कैनोपी के नीचे विराजमान हैं, जहा पहले कभी सम्राट जॉर्ज की प्रतिमा हुआ करती थी। भारतीय नौसेना के चिन्ह को बदलकर उसमें तिरंगे को समाहित किया गया है। औपनिवेशिक युग के 1500 कानून अब कानून की पुस्तकों में नहीं हैं। नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक विरासत से मुक्त किया है। यह एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी बदलाव है कि 'दंड' संहिता अब 'न्याय' संहिता बन गई है, जो पीड़ितों की हितों की रक्षा, अभियोजन को कुशलतापूर्वक पूर्ण करने और अन्य कई पहलुओं में सुधार पर केंद्रित है। लोक अधिकारियों में सॉफ्ट स्किल्स, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सांस्कृतिक क्षमता का विकास महत्वपूर्ण है ताकि अधिकारी हाशिये पर मौजूद कमजोर वर्ग की कठिनाइयों को समझ कर ऐसी नीतियां तैयार करें जिनसे चुनौतियों का समा धान हो। जैसे–जैसे हम शासन के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, डेटा हमारे निर्णय–निर्माण प्रक्रियाओं के अग्रिम पंक्ति में होना चाहिए। विभिन्न कल्याण कारी नीतियों के प्रभाव को समझने के लिए प्रमाण आधारित अध्ययन आवश्यक हैं। अनुभवजन्य साक्ष्यों पर आधारित मूल्यांकन न केवल हमारे संस्थानों की विश्वसनीयता को बढ़ाएगा बल्कि शासन में सार्वजनिक विश्वास को भी बरकरार रखेगा। यह उन लोगों के लिए एक उपयुक्त जवाब भी साबित होगा।

राष्ट्रपति मुर्मू ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को सराहा

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व जहां संघर्ष और जलवायु संकट का सामना कर रहा है, ऐसे समय में बौद्ध धर्म के पास मानव समुदाय को देने के लिए बहुत कुछ है। इनकी शिक्षाएं संकट के समय काफी उपयोगी हैं। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में करुणा शब्द शामिल है, जिसकी विश्व को आज जरूरत है।

शांति और अहिंसा का संदेश दे रहा बौद्ध धर्म

राष्ट्रपति ने कहा कि आज दुनिया कई मोर्चों पर संकट का सामना कर रही है। इस वक्त आपसी संघर्ष के साथ ही जलवायु संकट भी खूब बढ़

रहा है। ऐसे वक्त में बौद्ध धर्म के पास मानव जाति को देने के लिए बहुत कुछ है। बौद्ध धर्म के अलग–अलग स्कूल संप्रदायवाद का मुकाबला करना सिखा रहे हैं। धर्म का मुख्य संदेश शांति और अहिंसा को फैलाना है। उन्होंने कहा कि एशिया को मजबूत करने के लिए बुद्ध धम्म के बारे में भी चर्चा की जानी चाहिए। बुद्ध धम्म एशिया और विश्व में वास्तविक शांति ला सकता है। यह शांति ऐसी है जो न केवल शारीरिक हिंसा से मुक्त है, बल्कि लालच और घृणा से भी दूर करती है।

बौद्ध साहित्य हमारी साझा विरासत

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पुराने समय में चीनी और अन्य विद्वानों द्वारा अनुवादित की गईं बौद्ध साहित्यिक कृतियों ने मूल कृतियों के नष्ट हो जाने के बाद भी संरक्षण में योगदान दिया। बौद्ध साहित्य हमारी साझा विरासत है। पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने पर राष्ट्रपति ने कहा कि इससे दोनों भाषाओं के ग्रंथों के संरक्षण और पुनरोद्धार में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन बुद्ध की शिक्षाओं की हमारी साझा विरासत के आधार पर सहयोग को मजबूत करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

संस्कृति मंत्रालय करा रहा सम्मेलन

दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन संस्कृति मंत्रालय की ओर से अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (आईबीसी) के सहयोग से किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका है।

महिलाओं के लिए अच्छी खबर, एमपी की मोहन सरकार ने बढ़ाया आरक्षण

मध्य प्रदेश, एजेंसी। मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आवंटित आरक्षण कोटा में वृद्धि की घोषणा की। जारी की गई जानकारी के मुताबिक, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने वाली सरकार ने इसमें 2 फीसदी अतिरिक्त बढ़ोतरी कर दी है, जिससे महिलाओं का कोटा 35 फीसदी हो गया है। सरकार के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की ब्रीफिंग के दौरान इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं के तहत सभी भर्तियों में

आरक्षण (महिलाओं के लिए) 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। यह निर्णय पहले लिया गया था, और इसे आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। गौरतलब है कि उपमुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट बैठक के दौरान लिए गए अन्य बड़े फैसलों के बारे में भी विस्तार से बताया. शुरुआत करते हुए मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने राज्य में 254 नए उर्वरक बिक्री केंद्र खोलने को मंजूरी दे दी है। किसानों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी और नकद भुगतान पर आसानी से खाद मिलेगी। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने कुल 830 मेगावाट इकाइयों (प्रत्येक 205 मेगावाट के दो बिजली संयंत्र और 210 मेगावाट के दो अन्य संयंत्र) की पिछली बिजली संयंत्र इकाइयों को बंद करके सारनी में 660 मेगावाट का क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की भी मंजूरी दे दी है।

9 जजों की संविधान पीठ का ऐतिहासिक फैसला, हर निजी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकती सरकार

नई दिल्ली, एजेसी। सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में भारत के मुख्य न्याया धीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों

वाली पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाले प्रत्येक निजी संपत्ति संसाधन को संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत भौतिक संसाधन नहीं कहा जा सकता है। नौ जजों की पीठ में जस्टिस हृषिकेश रॉय, बीवी नागरत्ना, जेबी पारदीवाला, सुधांशु धूलिया, मनोज मिश्रा, राजेश बिंदल, सतीश चंद्र शर्मा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल थे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि तीन जजमेंट हैं, मेरा और 6 जजों का। जस्टिस नागरत्ना का आंशिक सहमति वाला और जस्टिस धुलिया का असहमति वाला।

पीठ द्वारा 1 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि किसी व्यक्ति के प्रत्येक निजी संसाधन को समुदाय के भौतिक संसाधन के हिस्से के रूप में रखना दूर की कौड़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उन निवेशकों को भी डरा देगा जो उन्हें मिलने वाली सुरक्षा के स्तर से सावधान होंगे। यह टिप्पणी तब आई जब वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि विभिन्न संविधान पीठों के 16 फैसलों में निजी संपत्ति और निजी संसाधनों को शामिल करने के लिए भौतिक संसाधनों की लगातार व्याख्या की गई है। शीर्ष अदालत ने इससे संबंधित एक संदर्भ पर सुनवाई की।

जेएमएम-कांग्रेस अब फुस्स हो चुके पटाखे - राजनाथ सिंह

झारखंड, एजेंसी। रांची में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री के प्रस्तावक रहे मंडल मुर्मू के भाजपा में शामिल होने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि झारखंड में कौन सरकार बनाने जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मंडल मुर्मू ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावक के रूप में अपना नाम वापस ले लिया है और बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। मंडल मुर्मू समझ गये कि झामुमो की नैया डूब रही है। साफ है कि एनडीए यहां सरकार बनाएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि झामुमो, कांग्रेस, राजद अब फुस्स हो चुके पटाखे हैं, भाजपा एक शक्तिशाली रॉकेट है जो झारखंड को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अपना हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि जेएमएम का मतलब 'जमकर मलाई मारो' है, यह आदिवासियों का खून चूसता है। राजनाथ सिंह ने सवाल करते हुए कहा कि मैं हेमंत सोरेन से पूछता हूं कि घुसपैठिए झारखंड में क्यों आ रहे हैं?, आदिवासी आबादी 28 प्रतिशत तक क्यों सिमट गई? अब तक यहाँ के सात मुख्यमंत्रियों में से तीन को जेल जाना पड़ा है। इनमें एक भी मुख्यमंत्री भाजपा का नहीं है। भाजपा ने हमेशा ठीक ढंग से सरकार चलाई है। जेएमएम की सरकार जब जब आयी भ्रष्टाचार बढ़ा है। जेएमएम, कांग्रेस और राजद

उन्होंने लोगों से अपील की कि भाजपा को दो कार्यकाल दीजिए, झारखंड विकसित राज्यों की कतार में होगा। भाजपा नेता ने कहा कि झारखंड में ने झारखंड को ठगा है। ये दल इस प्रदेश के विकास में स्पीडब्रेकर बने हुए हैं। ये स्पीडब्रेकर इस बार के चुनावों में तोड़ दीजिये। राजनाथ ने कहा कि देशभर में करीब 60 हजार आदिवासी गांवों के विकास के लिए विशेष योजना की घोषणा की गई है। आदिवासियों में भी जो पिछड़े हैं उनके विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना चलाई है। झारखंड में सरकार बनने पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। घुसपैठियों द्वारा कब्जाई आदिवासी जमीन को वापस लौटाने के लिए कानून बनाएंगे। वरिष्ठ नेता ने कहा कि झारखंड में सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को झारखंड की सभी महिलाओं के बैंक खाते में 2100 रुपये प्रदान करेंगे। झारखंड में सरकार बनने पर हम लोग फूलो–झानो पढ़ो बिटिया योजना के तहत राज्य के गरीब और पिछड़े वर्ग की प्रत्येक बालिका को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 370 अब इतिहास, इसके हिमायती दिन में तारे देखना बंद करें - रविशंकर प्रसाद

पटना, एजेंसी। जम्मू–कश्मीर विधानसभा में सोमवार को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के विधायक वहीद पारा ने केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के विरोध में प्रस्ताव पेश किया। इस पर विधानसभा में हंगामा हो गया। भाजपा सदस्यों ने इस प्रस्ताव का जमकर विरोध किया। पार्टी के कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 अब इतिहास हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन चुका है। इसे संसद द्वारा दो–तिहाई बहुमत से पारित करके संविधान में संशोधन किया गया है। कश्मीर में अब शांति है और वहां पूंजी निवेश भी हो रहा है। जो लोग इसे दोबारा लागू करने की बातें करते हैं, उन्हें हकीकत से मुंह मोड़ना बंद कर देना चाहिए। ऐसे लोग दिन में तारे देखना बंद करें।

अनुच्छेद 370 अब कभी भी लागू नहीं होगा। उन्होंने बिहार में छठ पूजा के पूर्व घाटों का निरीक्षण भी किया।

उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के पटना साहिब के दीघा घाट, पाटीपुल घाट, दीघा 93, दीघा 83 घाट, जेपी घाट, एनआईटी घाट, कृष्णा घाट, कंगन घाट, भद्र घाट, रानी घाट सहित अन्य घाटों का भ्रमण किया। उनके साथ पटना डीडीसी एवं नगर निगम के पदाधिकारी, पटना सिटी के एसडीएम और एनडीआरएफ की सुरक्षा दस्ता के अधिकारी भी मौजूद थे।

अटल वाजपेयी का नजरिया अपनाया गया होता तो जम्मू-कश्मीर की यह हालत नहीं होती - सीएम उमर

श्रीनगर, एजेसी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नजरिया अपनाया होता तो जम्मू–कश्मीर की यह हालत नहीं होती। जम्मू–कश्मीर विधानसभा में श्रद्धांजलि सभा के दौरान अब्दुल्ला ने पूर्व प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि वाजपेयी ने ''हमेशा जम्मू–कश्मीर में स्थिति को सुधारने की कोशिश की।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वाजपेयी 1999 में पहली दिल्ली–लाहौर बस से पाकिस्तान गए थे, तो उन्होंने मीनार– ए–पाकिस्तान का दौरा किया था जो 'आसान नहीं 'था। सदन के नेता अब्दुल्ला ने कहा, ''फिर वह सरहद पर खड़े हो गए और कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। वाजपेयी ने कहा था कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने असफलताओं का

सामना करने के बावजूद बार–बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया।'' अब्दुल्ला ने कहा, ''मैं उन्हें (वाजपेयी को) जानता हूं और उनकी मंत्रिपरिषद के एक मंत्री के रूप में उनके साथ काम किया है। जब हम वाजपेयी को याद करते हैं, तो हम उन्हें जम्मू–कश्मीर के संदर्भ में याद करते हैं। उन्होंने हमेशा जम्मू–कश्मीर में स्थिति को सुधारने की कोशिश की, उन्होंने तनाव कम करने की कोशिश की।'' अब्दुल्ला ने कहा, ''उन्होंने नियंत्रण रेखा (एलओसी) के आर – पार के रास्तों को खोलने के लिए काम किया जो बाद में फिर से बंद हो गए। वह लोगों को करीब लाना चाहते थे। उन्होंने नागरिक समाज को करीब लाने की कोशिश की।

आज हमें अलग रखने की कोशिश की जा रही है।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर वाजपेयी का नजरिया अपनाया गया होता तो जम्मू–कश्मीर की ''यह हालत नहीं होती।'' पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने कहा, ''मुखर्जी के पास कोई 'गॉडफादर' नहीं था।

महाराष्ट्र जीतने के लिए दलित–ओबीसी वोटों पर एकनाथ शिंदे सरकार की नजर

हरियाणा और जम्मू–कश्मीर के विधानसभा चुनाव नतीजों ने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को सियासी बूस्टर दिया है।

सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली भाजपा–शिवसेना –एनसीपी की गठबंधन सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी और दलित समुदाय को साधने के लिए बड़ा सियासी दांव चल दिया है। हरियाणा की सियासी बाजी जीतने के बाद अब उसी तर्ज पर पार्टी महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई फतह करने का प्लान बनाया है। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या शिंदे सरकार महाराष्ट्र में जीत का परचम लहरा पाएगी। शिंदे सरकार ने राज्य विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य अनुसूचित आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र विधानमंडल के अगले सत्र में अध्यादेश पेश किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार से ओबीसी की क्रीमी लेयर की तय सीमा 8 से बढ़ाकर 15 लाख करने की मांग के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। बता दें कि ओबीसी को आरक्षण के लिए गैर क्रीमी लेयर लेना पड़ता है।

शिंदे सरकार ने चला सियासी दांव

जिस तरह विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिंदे सरकार ने दोनों अहम फैसले लिए हैं। ऐसे में इसे भाजपा–शिवसेना और एनसीपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। शिंद कैबिनेट के यह दोनों ही फैसले इसलिए भी अहम माने जा रहे हैं।

संपादकीय

चीन की धारणा

नए त्यौहारी मौसम का स्वाद स्पष्ट रूप से चीन–भारत मेल–मिलाप है और यह अच्छे उपाय के लिए है। 2014 से 2020 तक हमने जो यथोचित रूप से समृद्ध और, कहने की हिम्मत है, सुधरते रिश्ते देखे, उसके बाद चार साल से अधिक समय तक नकारात्मकता ने मुंह में कड़वाहट छोड़ दी। विश्लेषकों के लिए प्रलोभन 21 अक्टूबर, 2024 को घोषित समझौते के विवरण में सीधे कूदना और अंतिम सैनिक की चाल और स¬।ब पर सेना–से–सेना बैठक में कहे गए शब्दों तक कार्यान्वयन की निगरानी करने के पसंदीदा शगल में लिप्त होना है। वास्तव में इसे केवल इस व्यापक समझ के साथ छोड़ना पर्याप्त है कि कोर कमांडर स्तर की वार्ता के बीच जुड़ाव से अब तक अछूते दो क्षेत्र– डेमचोक और देपसांग– को विघटन की सुविधा के लिए संबोधित किया गया है और बाद में गश्ती को उन क्षेत्रों में फिर से जाने की अनुमति दी गई है जहां उन्हें रोका गया था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिसके बारे में अटकलें तब तक जारी रहेंगी जब तक कि सरकार द्वारा मीडिया द्वारा क्षेत्र के दौरे के साथ–साथ विस्तृत रिपोर्ट पारदर्शी रूप से सामने नहीं आ जाती। जिस मुद्दे पर हमें पूर्ण सहमति की आवश्यकता है, वह यह समझ है कि भारत और चीन के बीच कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में जो कुछ हुआ है, वह कोई परिवर्तनकारी घटनाक्रम नहीं है, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह प्रक्रिया कितनी दूर तक जाएगी, क्योंकि चीन की प्रवृत्ति विदेशी संबंधों को कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक घटनाओं के संग्रह के रूप में देखने की है। यह समझना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि चीन के दिल में परिवर्तन कहां से आया और चीन–भारत संबंधों के इस प्रकरण को चीनी नेतृत्व और थिंक टैंक किस तरह से देखेंगे। बस याद रखें कि सीमा पर अप्रैल–मई 2020 की स्थिति बहाल हो सकती है, जिसमें सभी आरक्षित बल और साधन थोड़े हटकर और स¬।ब से बहुत दूर नहीं होंगेय बुनियादी ढांचे के विकास को स्पष्ट रूप से वापस नहीं लाया जा सकता है। फिर भी, जो चीज रातोंरात बहाल नहीं की जा सकती, वह है दोनों देशों के बीच विकसित हुआ विश्वास और संकटों में संभावित राजनयिक अंतिम उपाय का विश्वास, यदि शीर्ष स्तर की सहमति से नहीं। चीन–भारत संबंधों में विकास को प्रभावित करने वाले कारक यूक्रेन और मध्य पूर्व में चल रहे संघर्षों के भू–राजनीतिक प्रभाव, विश्व व्यवस्था का आभासी पूर्व–पश्चिम विन्यास में उभरता विभाजन, चीनी अर्थव्यवस्था की गिरावट और भारत के अपने स्वयं के शक्ति आकांक्षा के साथ एक स्विंग राज्य के रूप में संभावित उदय से संबंधित हैं। इनसे भी अधिक व्यापक धारणा यह है कि चीन भारत के बारे में यह धारणा रखता है कि वह उच्च भू–राजनीतिक स्थिति में अपने उदय में संभावित बाधा बन सकता है। यह बाद की बात है जिसने संभवतः 2020 में चीन को बेचौन कर दिया। मैंने अक्सर लिखा है, कि डोकलाम गतिरोध, भारतीय सशस्त्र बलों का परिवर्तनकारी आधुनिकीकरण, 2016 और 2019 में नियंत्रण रेखा के पार किए गए नपे–तुले हमले और अनुच्छेद 370 को सक्रिय रूप से हटाने से चीन को एक ऐसा संदेश मिला जिसे उसने गलत समझा। भारत निश्चित रूप से सूरज के नीचे अपना स्थान तलाश रहा था यह सिर्फ एक संदेश था जिसे चीन ने बहुत ही अजीब तरीके से मापा। चार साल और उससे ज्यादा समय में जो कुछ बदला, वह शायद सिर्फ चीन की इच्छा नहीं थी, बल्कि आपसी रणनीतिक जरूरत थी। चीन के लिए आर्थिक जरूरत बाजारों की रणनीतिक इच्छा में प्रकट होने लगी थी, जो अगर रिश्ते में तालमेल नहीं होता, तो पहुँच में नहीं आते। भारत ने पहले ही चीन को एक खिलाड़ी के तौर पर आंशिक रूप से बाहर करने के लिए कार्रवाई की थीय शायद इससे आखिरकार नुकसान होने लगा था। द्विपक्षीय संबंधों में सुधार से व्यापार में वृद्धि हो सकती है, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। चीन भारत के बढ़ते बुनियादी ढांचे, तकनीक और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश कर सकता है, जिससे लाभ मिल सकता है और आर्थिक संबंध गहरे हो सकते हैं। भारत में विकास प्रक्रिया एक लंबे रास्ते पर हैय भारत और चीन के बीच एक स्थिर संबंध चीनी अर्थव्यवस्था को लगातार बढ़ावा देने के लिए सहायक हो सकता है, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को भी। रणनीतिक दृष्टि से, चीन–अमेरिका संबंधों से जुड़े मुद्दों पर चीन के प्रति भारत की शत्रुता की गारंटी भविष्य की स्थितियों में काफी हद तक कम हो सकती है, अगर भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक रूप से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ दिखने के बजाय कम विकल्पों पर ध्यान देता है। भारत ने उभरती हुई विश्व व्यवस्था के प्रति अपने दृष्टिकोण को उचित कुशलता से संभाला है। यूक्रेन और गाजा दोनों ही उग्र युद्धों पर, इसने बिना किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया के समान दूरी बनाए रखी है। यह बारीकियों को अच्छी तरह समझता है और किसी भी तरह से खुद को उलझाए नहीं है। यहां तक ष्किकि एक मध्यस्थ बनना भी ऐसा कुछ नहीं है जिसमें इसे जल्दबाजी में उलझना चाहिए। हालांकि यह दर्जा उसे अंतरराष्ट्रीय भूराजनीति में उच्च दर्जा दिला सकता है, लेकिन यह उसके भविष्य के रिश्तों में संभावित रूप से शर्मनाक भी हो सकता है। चीन एक संभावित महाशक्ति के रूप में अपने भविष्य की स्थिति के बारे में बेहद चिंतित है। भारत इस लक्ष्य के लिए एकमात्र बाधा नहीं है।

विभाजित अमेरिका अब चाकू की धार पर

आदित्य

अगर अमेरिकी राष्ट्रपतियों का चुनाव स्थानीय नहीं, बल्कि वैश्विक वोट से होता, तो ट्रम्प टावर्स की प्रसिद्धि वाले डोनाल्ड ट्रम्प के पास मंगलवार, 5 नवंबर को दुनिया भर में छा जाने का मौका होता। जैसी कि स्थिति है, उन्हें धरती पर सबसे बड़ी चाल–या–उपचार चयन से संतुष्ट होना होगा। जबकि व्हाइट हाउस में उनकी वापसी कई लोगों के लिए एक क्रूर ष्चालष् हो सकती है, आंशिक रूप से भारतीय कमला देवी हैरिस का चयन, जिसका सामना वे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मौजूदा राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपनी पहली विनाशकारी बहस के बाद भारी दबाव के बाद दौड़ से बाहर होने का फैसला किया है, का मतलब दुनिया भर में ष्उपहारष् हो सकता है। हालांकि ब्रिटेन, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे एंग्लो–स्फेरिक देशों ने 31 अक्टूबर को चाल–या–उपचार हेलोवीन अनुष्ठान मनाया, यह सादृश्य एक ऐसे चुनाव के लिए प्रासंगिक है जो अभी भी अनिश्चितता के चाकू की धार पर खड़ा है। एक दिन सुश्री हैरिस एक प्रतिशत से भी कम अंक से आगे चल रही हैंय अगले दिन श्री ट्रम्प आगे निकल रहे हैं। यह लुभावना क्लिफहैंगिंग दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देता है। हैलोवीन की रात फैंसी ड्रेस पहने युवा लोग घर–घर घूमे और बेखबर मेजबानों से ट्रिक या ट्रीट के विकल्प के बारे में पूछा। "ट्रीट" आमतौर पर किसी प्रकार की मिठाई होती है, हालांकि आजकल कुछ संस्कृतियों में इसके बदले पैसे दिए जाते हैं। "ट्रिक" का मतलब है धमकी, आमतौर पर अच्छे स्वभाव वाली, अगर कोई ट्रीट न मिले तो व्यक्ति या उसकी संपत्ति पर किसी तरह की हल्की–फुल्की शरारत करना। यह प्रथा अभी तक महत्वाकांक्षी भारत में व्यापक रूप से नहीं फैली है, जहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अरबपतियों की संख्या में वृद्धि ने दशहरा–दिवाली के त्यौहार को सिंगल–माल्ट व्हिस्की पेयरिंग, मास्करेड बॉल्स और "पब क्विज" के साथ मनाया। लेकिन यह मैक्सिको में फैल गया है, जहां इसे "कैलावेराइट" (स्पेनिश में कैलेवेरा का छोटा रूप, अंग्रेजी में "खोपड़ी") कहा जाता है, ताकि "ट्रिक या ट्रीट" के बजाय, बच्चे एक छोटी खोपड़ी मांगें। यह भयावह लगता है लेकिन "कैलावेराइट" का मतलब अब चॉकलेट में ढली एक छोटी खोपड़ी है। 5 नवंबर के विजेता को सात महत्वपूर्ण राज्यों में जीत हासिल करनी होगी, जिसमें पेंसिल्वेनिया (19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट के साथ), एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और नेवादा शामिल हैं, जिसे श्री बिडेन ने 2020 में बहुत कम अंतर से जीता था। फ्लोरिडा और ओहियो को कभी सीमांत माना जाता था, लेकिन अब वे सुरक्षित रिपब्लिकन क्षेत्र हैं। हालाँकि, 1948 में कुछ भी तय नहीं हुआ था। हर पंडित ने न्यूयॉर्क के रिपब्लिकन गवर्नर थॉमस ई. डेवी की भारी जीत की भविष्यवाणी की थी, जब तक कि मिसौरी के एक पूर्व किसान, हैरी एस. ट्रूमैन, एक डेमोक्रेट, ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति बनकर उन्हें गलत साबित नहीं कर

दिया। यह चुनाव और भी भयावह होने का खतरा है। अमेरिकी पहले से कहीं ज्यादा विभाजित हैं, श्री ट्रम्प लगातार घोषणा कर रहे हैं कि जो दांव पर लगा है वह अमेरिका की आत्मा है, इससे कम कुछ नहीं। हम सिर्फ कमला के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि आज रात यहाँ हमारे बहुत से राजनेता यह जानते हैंष् वे चिल्लाते हैं। उसका कोई मतलब नहीं है, वह सिर्फ एक जहाज है। मैकार्थीवाद के डायन–शिकार के बारे में वे विस्तार से बताते हैं हम जो या कमला से कहीं ज्यादा बड़ी और उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो एक विशाल, शातिर कट्टरपंथी–वाम मशीन है जो आज की डेमोक्रेटिक पार्टी को चलाती है। उदार मूल्यों के लिए उनके कथित खघ्तरे को भविष्य के भयावह भविष्य के रूप में पेश करना खतरे को बढ़ा–चढ़ाकर पेश कर सकता है। जैसे रिपब्लिकन की 27 अक्टूबर की मैडिसन स्क्वायर गार्डन रैली की तुलना 20 फरवरी, 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने से सात महीने पहले कुख्यात हिटलर समर्थक जर्मन–अमेरिकी रैली से करना। श्वेत वर्चस्व और अमेरिकी देशभक्ति को समर्पित एक आर्य ईसाई देश के अपने दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने के लिए जॉर्ज वाशिंगटन के जन्मदिन को चुनते हुए, 27 अक्टूबर के आयोजकों ने स्वस्तिक झंडों और सितारों और पट्टियों के साथ वाशिंगटन का एक विशाल चित्र लगाया। 20,000 से ज्यादा अमेरिकी नाजी समर्थक, जिनमें से कई सीग हील सलामी देने वाले तूफान सैनिकों के रूप में प्रच्छन्न थे, ने सुना कि यहूदी नियंत्रित प्रेस के बावजूद अमेरिका उन लोगों को वापस कर दिया जाएगा जिन्होंने इसे स्थापित किया थाष्। हिलेरी क्लिंटन ने दोनों घटनाओं के बीच समानताओं का उल्लेख किया। सुश्री हैरिस के उप–राष्ट्रपति चुने गए टिम वाल्ज ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने कहा, यह 1930 के दशक के मध्य में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हुई एक बड़ी रैली से बिल्कुल मिलता–जुलता है, उन्होंने श्री ट्रम्प पर जानबूझकर नकल करने का आरोप लगाया। इस आरोप को खारिज करने वाले रिपब्लिकनों को राहत मिली होगी जब अमेरिकी पेशेवर कुश्ती के महान आइकन हल्क होगन कुश्ती के संगीत के साथ सामने आए, कई सेकंड तक अपनी शर्ट उतारने की कोशिश की, और फिर दावा किय मुझे यहाँ कोई बदबूदार नाजी नहीं दिख रहा है। फिर भी, मैडिसन स्क्वायर गार्डन रैली में गुस्सा और कटुता ने मुख्य भूमिका निभाई, जो (ट्रम्प के कई अन्य कार्यक्रमों की तरह) नस्लवादी टिप्पणियों, अपमानजनक अपमान और अप्रवासियों के बारे में खतरनाक धमकियों से चिह्नित थी। भीतर के दुश्मन से लड़ने के अपने दावे को दोहराते हुए और फिर सेष्अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा निर्वासन कार्यक्रम शुरू करने का वादा करते हुए, श्री ट्रम्प ने बहुत, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ फोन कॉल समाप्त करने के बारे में असंगत बकवास के बीच बात की ताकि वह एलोन मस्क के रॉकेट में से एक को उतरते हुए देख सकें। हालाँकि श्री वाल्ज का यह दावा कि दोनों घटनाओं के बीच "सीधा समानता" है और यह आरोप कि श्री ट्रम्प ने "हिटलर की प्रशंसा की" की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन रिपोर्टें बताती हैं कि घंटों लंबी रैली का स्वर गहरा था। एक रेडियो होस्ट ने हिलेरी क्लिंटन को "बीमार कमीनी" बतायाय सुश्री हैरिस की नस्लीय पहचान का मजाक उड़ाया गयाय और श्री ट्रम्प के एक बचपन के दोस्त ने उन्हें "क्राइस्ट विरोधी" कहा। एक वक्ता ने 3.2 मिलियन अमेरिकी नागरिकों के घर प्यूर्टो रिको को "कचरे का द्वीप" बताया। विडंबना यह है कि दोनों पक्ष प्यूर्टो रिकान को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। पेंसिल्वेनिया के 580,000 लैटिनो मतदाताओं में से अधिकांश प्यूर्टो रिकान वंश के हैं, जैसा कि रिकी मार्टिन, इंस्टाग्राम पर 18 मिलियन से अधिक अनुयायियों वाले पॉप स्टार हैं, जिन्होंने एक पोस्ट में लिखा थारू "वे हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं। /kamalaharris को वोट दें।" आव्रजन के बारे में अपने लगातार बयानों को जारी रखते हुए, श्री ट्रम्प पूर्व राष्ट्रपति ने यह भी गलत कहा कि बिडेन प्रशासन के पास उत्तरी कैरोलिना में हाल ही में आए तूफान का जवाब देने के लिए पैसे नहीं थे क्योंकि ष्उन्होंने अपना सारा पैसा अवैध अप्रवासियों को लाने और उन्हें खूबसूरत जेट विमानों से उड़ाने में खर्च कर दियाष्। हालाँकि उनकी टिप्पणी अपमानजनक है, श्री ट्रम्प खुद मांग में हैं। उनके ब्रांड वाली लग्जरी संपत्तियों की चाहत कथित तौर पर न केवल मुंबई और पुणे में बल्कि गुड़गांव और कोलकाता में भी आसमान छू रही है। यह आकांक्षात्मक है, खासकर उन लोगों के बीच जो हाल ही में अमीर बने हैं। अडानी और अंबानी कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं ठुकरा सकते जो आकांक्षाओं को पूरा करता है। फिर भी, जिम्मेदार आम सहमति यह प्रतीत होती है कि भले ही कमला हैरिस एक शानदार राष्ट्रपति न बनें, लेकिन वह एक विनाशकारी राष्ट्रपति भी नहीं बनेंगी।

तभी हो पाएगा विकसित भारत का सपना साकार

प्रेमपाल

केंद्र सरकार ने अस्सी वर्ष से ज्यादा उम्र के अपने पेंशनधारियों के अनुकंपा भत्ते में 20 से 100 प्रतिशत तक वृद्धि करने की घोषणा की। यह अतिरिक्त पेंशन होगी। सरकार का यह फैसला चकित करता है। आखिर वह इतनी दयालुता क्यों दिखा रही है? क्या उसने ऐसा कोई अध्ययन किया कि 80 साल से अधिक आयु वाले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों की वित्तीय हालत अच्छी नहीं है? इस उम्र तक आते–आते तो लोगों की जरूरतें न्यूनतम हो जाती हैं, फिर अनुकंपा भत्ते में इतनी वृद्धि क्यों? वैसे मानवीय दृष्टिकोण से विचार करें तो बुजुर्गों, दिव्यांगों और गरीबों की चिंता करना हर कल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारी है और सरकारें उसे अपनी सामर्थ्य भर पूरा कर भी रही हैं, लेकिन जब खुशहाली के पैमाने पर हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तब हमें पहले नौजवान पीढ़ी, नवजात बच्चों, उनकी माताओं और मजदूरों की चिंता करनी चाहिए, न कि उन बुजुर्गों की, जिनका जीवन सरकारी नौकरी में पहले से ही सभी पैमाने पर देश के आम आदमी से कहीं अच्छा है। सरकारी नौकरी में रहते हुए कर्मचारियों को तमाम सुविधाएं मिलती हैं। रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें अच्छी–खासी पेंशन मिलती है। अभी हाल में सरकार ने तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता और बढ़ाया है। सभी सरकारी कर्मचारियों को मेडिकल सुविधाएं मुफ्त में मिलती हैं। रेलवे और कुछ अन्य विभागों में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को यात्रा के लिए सरकारी पास, तो रक्षा और दूसरी नौकरियों में रियायती दर पर सामान आदि मिलते हैं। नौकरी में रहते हुए उन्हें सरकारी घर, दफ्तर आने–जाने के लिए कार आदि की सुविधा, यात्रा भत्ता, लीव इनकैशमेंट, बोनस आदि मिलते हैं। केंद्रीय सेवाओं में लगभग 35 लाख सरकारी कर्मचारी और 70 लाख पेंशनधारी हैं। मेडिकल और दूसरी सुविधाओं की वजह से आज लोगों की औसत उम्र भी अच्छी हो गई है। यही कारण है कि सरकारी बजट में पेंशनधारियों का बोझ मौजूदा सरकारी कर्मचारियों से लगभग दोगुना है। इन्हीं सब वजहों से 2004 में सबकी सहमति से पुरानी पेंशन स्कीम के बजाय नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी। उसके प्रति असंतोष को देखते हुए सरकार सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई है। एक अच्छी लोक कल्याणकारी सरकार वह होती है, जो देश के हर नागरिक की चिंता करे। इसी देश में निजी क्षेत्र में पूरी उम्र गुजारने के बाद भी करोड़ों कर्मचारियों के लिए संतोषजनक न्यूनतम पेंशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन कर्मियों की न्यूनतम पेंशन मात्र एक हजार रुपये है। आखिर निजी क्षेत्र के कर्मियों को सरकारी कर्मियों जैसी पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? सरकारी कर्मचारी तो देश में मुश्किल से एक प्रतिशत हैं। आखिर 99 प्रतिशत जनता को देने के लिए सरकार के पास क्या है? आज किसान गांव छोड़कर शहरों में मजदूर बनने के लिए अभिशप्त हैं। क्या सरकार के पास घरों में काम करने वाली महिलाओं के लिए कोई स्कीम है? पिछले दिनों खबर आई कि सरकार अपनी महिला कर्मचारियों के लिए भी हर महीने माहवारी छुट्टी पर विचार कर रही है। क्या निजी कंपनियां अपने यहां काम करने वाली महिलाओं को ऐसी छुट्टी देंगी? सरकारी सेवाओं में कार्यरत महिलाओं के लिए 20 वर्ष पहले चाइल्ड केयर लीव शुरू हुई थी। वे अपने 18 वर्ष तक के बच्चों की पढ़ाई आदि के लिए दो वर्ष तक वेतन एवं सुविधाओं के साथ घर पर रह सकती हैं। अब पिता को भी कुछ राज्य सरकारें छुट्टी देने लगी हैं। पहले मातृ अवकाश तीन महीने का मिलता था, अब सरकारी कर्मचारियों को छह महीने मिलता है, जबकि मजदूर महिलाओं के बच्चे सड़कों और पार्कों में गर्मी एवं बरसात में घूमते रहते हैं। अगर केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकारें भी ऐसी रेवड़ियां बांटने की कोशिश करने लगीं तो फिर देश की आर्थिक स्थिति का क्या होगा? पंजाब और हिमाचल प्रदेश का उदाहरण हमारे सामने है। अच्छा तो यही होगा कि सरकारें बुनियादी ढांचे के साथ–साथ ऐसे उद्योगों में पूंजी लगाएं, जिनसे अधिक से अधिक रोजगार पैदा हों। बुजुर्गों की इतनी चिंता के बजाय नई पीढ़ी के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करना ज्यादा जरूरी है। सरकारी नौकरियों में भरपूर सुविधाएं और निजी एवं असंगठित क्षेत्र में सुविधाओं की कमी के समाज पर बुरे असर होते हैं। आज देश का हर युवा सरकारी नौकरी में जाना चाहता है। एक चपरासी की नौकरी के लिए इंजीनियरिंग, पीएचडी किए नौजवान आगे आते हैं। सरकारी नौकरियों की भर्ती में भ्रष्टाचार का कारण ऐसी ही सुविधाएं और रेवड़ियां भी हैं।

यही कारण है कि नेता चुनाव से पहले सरकारी नौकरियों की घोषणा सबसे पहले करते हैं। क्या निजी क्षेत्र के लोग सरकारी कर्मचारियों से कम काम करते हैं? क्या उनके काम की चुनौती कमतर है? क्या उन्हें सरकारी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं मिलती हैं? यदि नहीं तो क्यों? क्या सरकारी स्कूल के शिक्षक अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं? अब तो कालेज में पढ़ाने वाले भी अपने बच्चों को इंग्लैंड, कनाडा एवं अमेरिका भेजते हैं।

पिछले हफ्ते ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस बात पर चिंता जताई थी कि बच्चे पढ़ने विदेश भाग रहे हैं। पिछले वर्ष 14 लाख बच्चे पढ़ने के लिए बाहर गए। इसमें अरबों रुपये विदेश चले गए। ऐसे में संविधान में जिस समानता की बात की गई है, उसे ध्यान में रखते हुए सरकार केवल सरकारी कर्मचारियों के ही हितों की चिंता न करे। उसे सबका साथ–सबका विकास नारे के तहत सबकी चिंता करनी चाहिए। उसे यह संदेश नहीं देना चाहिए कि वह सरकारी कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए अधिक तत्पर और संवेदनशील है।

गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कनाडा के आरोप

संजय

कनाडा का यह आरोप कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह, उस उत्तरी अमेरिकी राष्ट्र में सिख प्रवासी समुदाय के खालिस्तान समर्थक सदस्यों की हत्या के लिए नई दिल्ली द्वारा कथित प्रयासों के पीछे मास्टरमाइंड हैं, दोनों देशों के बीच संबंधों में दरार को और गहरा करने की धमकी देता है। कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा संसद में देश की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्यों के समक्ष किया गया यह दावा पश्चिम में एक भरोसेमंद मित्र और कानून का पालन करने वाले राज्य के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयासों को भी दर्शाता है। अप्रत्याशित रूप से, भारत ने इस आरोप को खारिज कर दिया हैय विदेश मंत्रालय ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए एक कनाडाई राजनयिक को तलब किया। लेकिन यह नवीनतम घटना रेखांकित करती है कि नई दिल्ली और ओटावा के बीच संबंध एक खड़ी और फिसलन भरी ढलान पर हैं, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। भारत और कनाडा दोनों पहले ही एक–दूसरे के अधिकांश वरिष्ठ राजनयिकों को निष्कासित कर चुके हैंय इस प्रकार नई दिल्ली ने कनाडाई उच्चायोग में एक प्रतिनिधि के माध्यम से श्री शाह के खिलाफ आरोपों का अपना मजबूत खंडन किया। इस बीच, कनाडा का दृष्टिकोण दर्शाता है कि वह संबंधों को सुधारने का कोई इरादा नहीं रखता है।

आबादी बढ़ाने की अनावश्यक अपील

डॉ. जगदीप

गत दिनों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने–अपने राज्यों की घटती आबादी पर चिंता जताई। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र की बुजुर्ग होती आबादी की तरफ ध्यान दिलाया तो एमके स्टालिन ने आने वाले वर्षों में परिसीमन के बाद लोकसभा के सीटों पर पड़ने वाले इसके असर पर चिंता व्यक्त की। स्टालिन ने कहा कि हमारी आबादी कम हो रही है। इसका असर हमारी लोकसभा की सीटों पर भी पड़ेगा। इसलिए अब समय आ गया है कि नवविवाहित जोड़े अधिक बच्चे पैदा करें। वहीं आंध्र के सीएम नायडू ने कहा कि श्एक समय, मैंने परिवार नियोजन अपनाने को कहा था, लेकिन अब मैं लोगों से अपील कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करके जनसंख्या बढ़ाएं। दरअसल दक्षिण भारतीय राज्यों को लग रहा है कि बढ़ती जनसंख्या पर सफल नियंत्रण की वजह से उन्हें राजनीतिक और आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि उनके मुख्यमंत्री जनता से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनका यह आह्वान भारतीय संघीय लोकतांत्रिक ढांचे के लिए सही नहीं है। इसके भारत को दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दक्षिण भारतीय राज्य यह प्रचारित कर रहे हैं कि जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन से लोकसभा में उत्तर भारत के राज्यों का दबदबा और बढ़ जाएगा। परिसीमन आयोग के 1976 के आदेश के बाद लोकसभा सीटों की संख्या स्थिर कर दी गई थी और अभी यह 543 है। 2001 में श्जनसंख्या सीमित करने के उपायोंश के लिए 25 साल के लिए लोकसभा सीटों की संख्या एक बार फिर से फ्रीज कर दी गई थी। अब जनगणना के बाद परिसीमन की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि जनगणना के अनुसार परिसीमन की कवायद की जाएगी। आंध्र और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों की पहली चिंता लोकसभा सीटों के संदर्भ में 2029 से पहले होने वाले संभावित परिसीमन को लेकर है।

संभावना है कि इसके बाद लोकसभा की सीटों की मौजूदा संख्या 543 से बढ़कर 790 हो जाए। अगर जनसंख्या में बदलाव के आधार पर लोकसभा की सीटें तय की गईं तो पांच दक्षिण भारतीय राज्यों की 23 सीटें कम हो जाएंगी। वहीं यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीटों की संख्या में 35 की बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि इन पांच राज्यों में ही भारत की करीब आधी आबादी है। अगर परिसीमन आयोग लोकसभा सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं करता तो भी जनसंख्या के आधार पर पांच दक्षिणी राज्यों की 25 सीटें घट जाएंगी और ज्यादा जनसंख्या वाले पांचों राज्यों के खाते में 33 सीटें अधिक जुड़ जाएंगी। अगर परिसीमन आयोग तय करता है कि किसी भी राज्य की मौजूदा लोकसभा सीटों की संख्या कम नहीं होगी, लेकिन बड़ी आबादी वाले राज्यों को भी उसी के मुताबिक सीटें दी जाएंगी तो भी आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना को जहां 23 सीटें ही और मिलेंगी तथा केरल की सीट 20 पर ही सीमित रहेगी, लेकिन पांच बड़े राज्यों की लोकसभा सीटों की मौजूदा संख्या में 150 सीटों की बढ़ोतरी हो जाएगी। चूंकि राज्यों को केंद्रीय सहायता मिलने में आबादी की भी भूमिका होती है इसलिए दक्षिण के राज्य यह शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें आबादी पर नियंत्रण पाने के चलते नुकसान उठाना पड़ा रहा है और केंद्रीय फंड में उनकी हिस्सेदारी कम होती जा रही है। यह पूरी तौर पर सही नहीं, क्योंकि 13वें वित्त आयोग (2010–15) से लेकर 15वें वित्त आयोग (2021–26) की सिफारिशों के अनुसार दक्षिण भारतीय राज्यों की हिस्सेदारी घटी जरूर है, लेकिन इसमें बिहार और यूपी जैसे सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य भी शामिल हैं। जैसे तमिलनाडु की हिस्सेदारी पांच प्रतिशत से घटकर 4.1 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश की 6.9 प्रतिशत से चार प्रतिशत, कर्नाटक की 4.3 प्रतिशत से 3.6 प्रतिशत और केरल की 2.3 प्रतिशत से 1.9 प्रतिशत हुई है। वहीं यूपी की हिस्सेदारी 19.7 प्रतिशत से घटकर 17.9 प्रतिशत और बिहार की 10.9 प्रतिशत से 10.1 प्रतिशत हुई है।

ज्यादा आबादी वाले राज्यों में सिर्फ मध्य प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान के केंद्रीय फंड में ही इजाफा हुआ है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें अगले वित्त वर्ष से लागू होनी हैं। इसमें भले ही प्रत्येक राज्य को मिलने वाली फंडिंग में वृद्धि हो रही हो, लेकिन सापेक्ष हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है। राज्यों की हिस्सेदारी तय करने के फार्मूले में जनसंख्या का भार पहले के 80–90 प्रतिशत से गिरकर 15 प्रतिशत हो गया है। 14वें वित्त आयोग ने सरकारी राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी की गणना करने के लिए श्जनसांख्यिकीय परिवर्तनश मानदंड यानी प्रवासन और आयु संरचना का उपयोग किया था। इससे आंध्र और तमिलनाडु की हिस्सेदारी में गिरावट आई।

15वें वित्त आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए श्दंडितश किए जाने पर राज्यों के बीच चिंताओं को दूर करने के लिए ही श्जनसांख्यिकीय प्रदर्शनश का एक मानदंड जोड़ा। दक्षिण के राज्य यह भी न भूलें कि आटोमोबाइल से लेकर साफ्ट ड्रिंक, स्मार्ट फोन से लेकर कपड़े के उत्पादन में अगर दक्षिण भारत का बड़ा योगदान है तो इस सबकी खपत सबसे ज्यादा उत्तर भारतीय बाजारों में ही होती है। इससे ही उनके राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है। दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए उत्तर भारत के ज्यादा आबादी वाले राज्य मजदूरों के आपूर्तिकर्ता की भी भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें आबादी बढ़ाने की अपील करने के स्थान पर उत्तर भारत की आबादी का उपयोग करना चाहिए। उत्तर भारत के मजदूर दक्षिण के राज्यों में जाकर उनके राजस्व में ही योगदान दे रहे हैं। इसलिए दक्षिण भारतीय राज्यों का आबादी बढ़ाने पर जो जोर है, उसके तात्कालिक फायदे तो हो सकते हैं, लेकिन आगे चलकर ज्यादा आबादी की जो परेशानियां बड़े राज्य झेल रहे हैं, वे उन्हीं भी झेलनी पड़ सकती हैं।

विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय पारंपरिक कार्यक्रमों के साथ गोमती महोत्सव हुआ संपन्न

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था मां फाउंडेशन व फर्स्ट वन रिहैब फाउंडेशन द्वारा गोमती नदी के प्रतिमा विसर्जन घाट पर आयोजित गोमती महोत्सव की समापन संध्या पर संस्कृतिक कार्यक्रमों को देख झूम उठे श्रोतागण। कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि गिरीश चंद्र यादव मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा, संस्था के प्रधान संरक्षक व व्यापारी नेता इन्द्रभान सिंह श्इंदुश डा. मधुकर तिवारी व पप्पू माली ने सामुहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया तत्पश्चात सेवा भारती द्वारा आयोजित राम कथा की सफलता की कामना से साथ 1111 आटे से निर्मित दीप दान आदि गंगा माँ गोमती में किया गया। संस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति अन्य राज्य,जनपदों सहित जौनपुर के कलाकारों द्वारा प्रचलित लोक कला, लोक संगीत,लोक विधाओं का प्रदर्शन किया गया जिसे देखकर श्रोता व अतिथि मंत्रमुग्ध हो उठे जिसमें प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक रविंद्र सिंह ज्योति, रोहतास बिहार से आई भजन गायिका मंदाकिनी मिश्रा, देवरिया से आए सुर संग्राम फेम राकेश तिवारी, सविता मौर्य गुंजन, सेजल ठाकुर वाराणसी, नीतेश सिंह रशिक, अवधि स्टार अनुराग पंडित, सूफी गायक जुबेर खान ने प्रस्तुति दी वहीं डी.बी.यस. इंटर कॉलेज की छात्र एवं छात्राओं द्वारा हिंदी व संस्कृत भाषा में सामुहिक रूप से गायन प्रस्तुत किया गया जिसे दर्शकों ने खूब सराहा वहीं पिक्टोरियल डांस ग्रुप की राजस्थानी प्रस्तुति घूमर नृत्य ने हर किसी का दिल जीत लिया । सांस्कृतिक क्षेत्र में अपने विधा का लोहा मनवाने वाले अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक रविंद्र सिंह श्ज्योतिश लेखक मृत्युंजय सिंह श्सिप्पीश, मुकेश अस्थान, मनोज दुबे श्मंजुलश, संगीत घराने से पंडित गोविंद मिश्रा व सामाजिक क्षेत्र में विशिष्ट कार्य कर रहे डॉ. आलोक सिंह, अतुल सिंह व विकास तिवारी श्शांडिल्यश को सम्मानित किया गया। आयोजक संस्था संरक्षक पप्पू माली व वरिष्ठ पत्रकार डॉ मधुकर तिवारी, उपाध्यक्ष सुधांशु सिंह, प्रणविजय सिंह, अजय यादव व नित्यानंद पांडेय ने समस्त आगंतुकों का स्वागत किया पत्रकार संजय अस्थाना, पत्रकार दीपक श्रीवास्तव, जिग्नेश मौर्य,अगम यादव, मोहित उपाध्याय, संतोष यादव ने आभार व्यक्त किया व संचालन मिमिक्री आर्टिस्ट मनीष रावत व सलमान शेख ने संयुक्त रूप से किया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉ.मनोज सिंह वत्स, निखिलेश सिंह, डॉ. आलोक यादव, डॉ.उत्तम गुप्ता, डॉ.रोबिन सिंह, बंदेश सिंह,देवेन्द्र खरे, महफूज अली सिद्दीकी, छोटेलाल श्रीमाली, सूरज सोनी डॉ.अपूर्व सिंह, चंद्रभान सिंह, राकेश सिंह, विनय सिंह, आदि लोग उपस्थित रहे।

07 नवम्बर 2024 को विकास खण्ड सिरकोनी में रोजगार मेला का आयोजन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उ0प्र0 एवं जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जिला सेवायोजन कार्यालय जौनपुर के तत्वाधान में 07 नवम्बर 2024 को प्रातः 10 बजे विकास खण्ड सिरकोनी परिसर जौनपुर में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। जिसमें विभिन्न निजी क्षेत्र की कम्पनियों के द्वारा हाईस्कूल, इण्टर, आई0टी0आई0 एवं स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र की कम्पनियों में सेवायोजित कराये जाने हेतु रोजगार मेला आयोजित किया जायेंगा। जिसमें अभ्यर्थी प्रतिभाग करते हुए साक्षात्कार के माध्यम से योग्यतानुसार विभिन्न पदों पर रोजगार प्राप्त कर सकते है।

जिला सेवायोजन अधिकारी एवं सहायक सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेला में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति आई0डी0प्रुफ सहित एवं वेब पोर्टल https://rojgaar sangam .up.gov.n पर जॉबसीकर के रूप में पंजीकरण उपरांत आवेदन करते हुए रोजगार हेतु अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करें।

लखनऊ में आयोजित भारत महोत्सव के शुभारंभ और समापन समारोह में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक और संगीत प्रशिक्षक अविजित श्रीवास्तव के साथ मुंबई निवासी आद्या, अद्विका और अमन ने बेहतरीन संगीत से समां बांधा

मृत्युंजय प्रताप सिंह

लखनऊ। लखनऊ में प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले भव्य आयोजन भारत महोत्सव में शुभारंभ से समापन समारोह तक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था सुर ताल संगम के कलाकारों तथा प्रमुख पदाधिकारियों ने शानदार संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बारह दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के महोत्सव में प्रतिदिन सांस्कृतिक मंच पर देश के विभिन्न हिस्सों से आए सुप्रसिद्ध कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कला प्रदर्शन किया। इसी श्रृंखला में जानी मानी दूरदर्शन एवं आकाशवाणी अनुमोदित गायिका डॉ जया श्रीवास्तव के निर्देशन में सुर ताल संगम संस्था के मुख्य कलाकारों तथा पदाधिकारियों ने अपनी मनमोहक संगीतमय प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारत महोत्सव के भव्य मंच पर डॉ जया श्रीवास्तव के निर्देशन में एक विशेष आकर्षण नवरस गायन

प्रतियोगिता में भी सुर ताल संगम के कलाकारों का पूर्ण वर्चस्व कायम रहा, जिसमें सात वर्षीय अद्विका श्रीवास्तव, शुभी राजपूत तथा रमन श्रीवास्तव ने प्रथम पुरस्कार जीता। द्वितीय स्थान पर युविका पांडेय, आशीष रावत और सुशील सिंह राठौर दावेदार बने। तीसरा पुरस्कार शरण्या सिंह, हिमांशु एवं चंदन रैतानी को प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल में प्रमुख भूमिका अविजित श्रीवास्तव, ओंकार शंखधर, प्रशांत स्वरूप, सीमा विरमानी सहित मुंबई से आमंत्रित लोकप्रिय गायिका आद्या श्रीवास्तव ने निभाई।अध्यक्ष श्री विनोद कुमार सिंह, उपाध्यक्ष एन बी सिंह और सांस्कृतिक सचिव श्रीमती प्रिया पाल ने सभी विजेताओं और जजेज को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

गायत्री महायज्ञ की निकाली गई कलश यात्रा

पॉच दिवसीय पावन प्रज्ञा पुराण कथा एवं गायत्री महायज्ञ प्रारम्भ

सुजानगंज (जौनपुर)। क्षेत्र के दिव्य गायत्री मंदिर एंव गोसाई बीर बाबा धाम पेट्रोल टंकी के पूरब सुजानगंज मे पावन प्रज्ञा पुराण कथा एंव गायत्री महायज्ञ के प्रथम दिन गायत्री परिवार के आचार्यो द्वारा विधि–विधान से कलश पूजन कराकर गायत्री भक्तो एंव सरोज विधाशंकर ग्रूप आफ कालेज एवं महाविद्यालय के आचार्यो एवं छात्राओ द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई । जिसमे गायत्री शक्तिपीठ से निकल फरीदाबाद पूरा, श्री गौरीशंकर धाम , बालवरगंज , सुजानगंज बाजार होते हुए गायत्री शक्तिपीठ पर सम्पन्न हुई। कलश यात्रा के दौरान माता गायत्री के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूज उठा. कलश यात्रा के दौरान माता के भक्तो द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा किया गया प्रति दिन दो बजे से सायं पाँच बजे तक शांति कुंज हरिद्वार से पधारे युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के प्रज्ञा पुत्रों द्वारा संगीत मे कथा संपन्न होगा. यह कथा 06 नवंबर 2024 से 10 नवंबर 2024 तक चलेगा। इस अवसर पं0 विधाशंकर तिवारी, सरोज कुमारी, डा0 विधासागर त्रिपाठी,डा0 सुषमा त्रिपाठी , विजय कुमार तिवारी आदि उपस्थित रहे।

गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल में प्रो0 वी0 के0 अग्निहोत्री ने आयुर्वेद के विषय में चर्चा की

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लखनऊ में नवप्रवेशित ठ।डै छात्र छात्राओं का NCISM द्वारा निर्देशित Transsitional Curriculum का शुभारम्भ हुआ । इस कार्यक्रम में सेवानिवृत प्रो० वी ० के ० अग्निहोत्री (राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय ऋषिकेश हरिद्वार) ने अपने Motivation speech में आयुर्वेद के विषय में चर्चा की। इस डवजपअंजपवदंस चममबी से नव प्रवेशित छात्र छात्राओं का ज्ञान वर्धन, मार्ग दर्शन एवं उत्साह वर्धन भी हुआ। कार्यक्रम का शुभारम्भ भगवान धन्वन्तरि की वन्दना, दीप प्रज्ज्वलन, एवं पुष्प माला अर्पण के साथ प्रारम्भ हुआ। इस कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य प्रो० अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव, डायरेक्टर दृडॉ० आलोक जैन, प्रो० अरविंद कुमार श्रीवास्तव,प्रो० सुनील कुमार गुप्ता,प्रो० अमरजीत यादव, प्रो० अवधेश बरनवाल , प्रो० जॉली सक्सेना,डॉ० पुजा गुप्ता, डॉ० प्रभुनाथ दास, डॉ० प्रवीण कुमार मिश्र, डॉ०

सौरभ तिवारी, डॉ० दीपक सुधि, डॉ० पद्मजा, डॉ० अदित्या, डॉ० प्रदीप कुमार, डॉ० वैशाख आदि उपस्थित रहें।

दुर्लभ पांडुलिपियों को संरक्षित किया जाएगा – प्रोफेसर आलोक राय

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के टैगोर पुस्तकालय में लाइब्रेरी कमेटी की बैठक कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में वर्तमान में कार्यरत उन सभी शिक्षकों की पुस्तक डिस्प्ले में रखी जाएगी जिन्होंने पुस्तक लेखन का कार्य किया है इससे यहां अध्यनरत छात्र छात्राएं इस सुविधा का भी उपभोग कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त निम्न बिंदुओं पर भी चर्चा हुई–

1. वीड आउट पॉलिसी के अंतर्गत जो पुस्तकें क्षतिग्रस्त हो गई है और बहुत पुरानी हैं, प्रयोग में नहीं लाई जा सकती हैं, उनको छात्रों के लिए डिस्प्ले में लगाई जाएगी, उनको उपलब्ध कराई जाएंगी और महाविद्यालयों और शिक्षकों को दे दी जाएंगी।

2. ई रिसोर्सेज में परिवर्तन लाते हुए नए ई रिसोर्सेज, डेटा बेस, एवं सॉफ्टवेयर छात्रों और शिक्षकों को उपलब्ध कराया जाएगा।

3. रीडिंग रूम में ऐसे अलमारी की व्यवस्था की जाएगी जिसमें वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए पुस्तकों को रखा जाएगा जो बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो।

4. पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों के ऊपर आर एफ आईडी लगाई जाएगी।

5. दुर्लभ पांडुलिपियों को संरक्षित किया जाएगा जिससे उनका क्षय होने से रोका जा सके।

कुलपति जी ने कहा की लाइब्रेरी को इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए जिससे उसका अधिक से अधिक उपयोग छात्र और शिक्षक कर सकें। मानद लाइब्रेरियन टैगोर लाइब्रेरी प्रोफेसर केया पांडेय ने कहा कि कुलपति जी के नेतृत्व में लगभग 6 वर्षों के पश्चात होने वाले इस लाइब्रेरी कमेटी से टैगोर पुस्तकालय को विकसित करने में अत्यधिक सहायता होगी।

श्री गुरु सिंह सभा ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाका हिंडोला में प्रबंधक कमेटी के चुनाव संपन्न

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। श्री गुरु सिंह सभा ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाका हिंडोला लखनऊ में प्रबंधक कमेटी के चुनाव की संपूर्ण हुआ जिसमें अध्यक्ष पद पर डा. अमरजोत सिंह बग्गा, महामंत्री पद पर मनजीत सिंह बंटी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तरनजीत सिंह मक्कड़ उपाध्यक्ष हरमिंदर सिंह टीटू, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह (मोनू बक्शी) एवं पी. आर.ओ. आज्ञापाल सिंह, धार्मिक सेक्रेटरी सरबजीत सिंह, राजिन्दर सिंह (पप्पू) एवं समस्त टीम पूर्ण निर्वाचित हुई।

गंगा में 45 मोटरबोट करेगी गश्त, 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, सुरक्षा को प्रशासन तैयार

वाराणसी, संवाददाता। छठ के मद्देनजर सात नवंबर की शाम और आठ नवंबर की सुबह सामने घाट से लेकर नमो घाट तक और रामनगर की ओर गंगा में जल पुलिस, एनडीआरएफ और पीएसी बाढ़ राहत दल की 45 मोटरबोट गश्त करेंगी। 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी गंगा घाटों पर तैनात रहेंगे। गंगा में नगर निगम की ओर से बैरिकेडिंग कराई गई है। जल पुलिस, पीएसी, बाढ़ राहत दल और 11 एनडीआरएफ के जवानों को अतिरिक्त सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। नाविकों को कहा गया है कि वह लाइफ जैकेट के साथ ही अन्य जीवन रक्षक उपकरणों के साथ ही यात्रियों को नाव पर बैठाएं। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कहा कि कमिश्नरेट के तीनों जोन के डीसीपी को घाटों से लेकर कुंडों–तालाबों पर सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था करने को कहा गया है। उन्होंने निर्देश दिया कि पुलिस स्थानीय गोताखोरों के संपर्क में रहे। पूजा समितियों के वॉलंटियर अपना परिचय पत्र पहन कर रहें। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर एंटी रोमियो स्क्वॉड की ड्यूटी लगाई जाए। जेबकतरों, उचक्कों और शोहदों की निगरानी के लिए सादे कपड़ों में भी महिला–पुरुष पुलिस कर्मी तैनात किए जाएं।

एनडीआरएफ आवश्यक उपकरणों के साथ रहेगी तैयार

11 एनडीआरएफ के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि गंगा में तैनात प्रत्येक टीम में हमारे 25 से 30 जवान रहेंगे। उन्हें जीवन रक्षक उपकरणों, रेस्क्यू मोटर बोट, वॉटर एंबुलेंस, लाइफ जैकेट, गोताखोर, पैरा मेडिकल, ऑक्सीजन सिलेंडर व अन्य आवश्यक बचाव उपकरणों से लैस किया गया है। बरेका के सूर्य सरोवर में भी एनडीआरएफ की टीमें तैनात रहेंगी।

शिव की नगरी में हुआ कृष्ण लीला का आयोजन

वाराणसी, संवाददाता। तुलसी घाट पर नाग नथैया लीला का अद्भुत आयोजन हुआ। इस लीला में कृष्ण रूपी कलाकार ने पहले क्रीड़ा किया उसके बाद यमुना रूपी गंगा में छलांग लगा दी बाहर आकर सबको दर्शन दिए और सभी ने हर हर महादेव का उद्घोष किया और लीला का समापन हुआ। आपको बता दें कि इस लीला को गोस्वामी तुलसीदास ने शुरू कराया था। कहा जाता है कि वृंदावन के कालीदह घाट पर कान्हा ने लीला की और यमुना से कालिया को उद्भाषित कर दिया। उसी तरह इस लीला का संदेश भी कालियानाग रूपी नालों को उद्भाषित कर गंगा को स्वच्छ करने का होता है। मान्यता है कि इस लीला को देखने के लिए लाखों की भीड़ होती है। इस लीला के महात्म्य सम्राट अकबर ने 1553 में इस लीला को देखने की इक्षा जताई और नौका से आकर इस लीला को देखा था। काशी नरेश का परिवार आज भी बजड़े पर सवार होकर इस लीला को देखता है हर साल यहां भक्तों की भारी भीड़ होती है इस बार भी भीड़ इकट्ठा हुई और जयकारा लगाया।

लीला का एक दृश्य

तुलसी घाट पर भक्तों की भीड़ इकट्ठा हुई और घाट पर बाल रूपी कलाकार सखाओं के साथ गेंद क्रीड़ा करता नजर आया। संकट मोचन मंदिर के महंत जब स्थान पर पहुंचे तो इन्होंने भी कृष्ण रूपी कलाकार को प्रणाम किया। फिर कृष्ण किनारे पर लगे कदंब के वृक्ष पर चढ़े और नदी में छलांग लगा दी। कुछ पलों के लिए सांसे थम गई। डमरूओं की ध्वनी गूंजी घंटे घड़ियाल बजे और नाग फन पर सवार होकर दर्शन मिला। सभी ने उद्घोष किया और आरती उतारी गई। कुछ लोग नौका पर सवार रहे सभी ने प्रणाम किया।

स्वास्थ्य विभाग के मानक पर खड़े नहीं उतर रहे भारी संख्या में निजी नर्सिंग होम व पैथोलॉजी

समय–समय पर उनके खिलाफ चलाया जाता है अभियान – डाक्टर संजय जैन

अयोध्या। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के रहमों करम पर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बिना पंजीकरण के निजी नर्सिंग अस्पताल व पैथोलॉजी संचालित हो रहे हैं।जिसके चलते यहां पर अपना इलाज व जांच करने आने वाले मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है साथ ही साथ उनसे मुँह मागा पैसा भी लिया जा रहा है।बताते चले कि कुछ ऐसे निजी चिकित्सालय व पैथोलॉजी का पंजीकरण भी स्वास्थ्य विभाग में नहीं हुआ।जो चोरी छिपे चल रही है।कुछ माह पूर्व डिलीवरी के दौरान कई प्रस्तावों की जान भी चली गई थी।जिसकी शिकायत मिलने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन स्वयं इसे गंभीरता से लेते हुए जांच भी किया था और सही पाए जाने पर उक्त निजी चिकित्सालय को सीज कर उसके संचालक के खिलाफ कार्यवाही किया था।परंतु इसके बावजूद भी अभी भी इस तरह से निजी चिकित्सालय व पैथोलॉजी चोरी छिपे चिकित्सा विभाग में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों के रहमो करम पर संचालित हो रहे है।इसी तरह से शहर से लेकर ग्रामीण

क्षेत्रों तक कई ऐसे पैथोलॉजी भी चोरी छिपे संचालित हो रहे हैं।जिनका पंजीकरण स्वास्थ्य विभाग में नहीं कराया गया है।यहां पर विभिन्न जांच व इलाज कराने आने वाले मरीजों से भारी भरकम पैसे की वसूली की जाती है। देखा जाए तो शहर के रिकाबगंज, नियांवा, जिला महिला चिकित्सालय के सामने, नाका, देव काली, बेनीगंज, के अलावा जिले के मसौधा, हैदरगंज, बीकापुर, कुमारगंज, तारुन,जाना बाजार, रामपुर भगन, रसूलाबाद, दर्शन नगर, सहित कई ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे–छोटे निजी अस्पताल व पैथोलॉजी संचालित हो रहे हैं।मजे की बात तो या यह भी है कि यह पैथोलॉजी और छोटे–छोटे अस्पताल ग्रामीण इलाकों में संबंधित संचालक अपने–अपने घरों में खोले हुए हैं।जिस पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्य शैली पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने बताया के शिकायत मिलने पर वह स्वयं और इसके अलावा आवश्यकता नुसार टीमें गठित कर बीच–बीच में उनके खिलाफ सघन अभियान चलाया जाता है। जो अस्पताल व पैथोलॉजी स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय किए गए मानक पर खड़े नहीं उतरते हैं तो उनके संचालकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाती है।

पत्नी और तीन बच्चों के कत्ल से दहली काशी परिवार को खत्म करने के बाद आरोपी पति फरार

वाराणसी, संवाददाता। वाराणसी के भदैनी इलाके में एक युवक ने पत्नी और तीन बच्चों की गोली मार कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घर छोड़ कर भागा हुआ है। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। सूचना पाकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वॉड के साथ भेलूपुर थाने की पुलिस मौके पर है। भदैनी स्थित पॉवर हाउस के सामने की गली में राजेंद्र गुप्ता अपनी पत्नी नीतू, बेटी गौरांगी और बेटों नवनेंद्र व सुबेंद्र के साथ रहता था। मंगलवार को पड़ोसियों ने राजेंद्र के घर का दरवाजा खुला नहीं देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची और राजेंद्र के घर गई तो नीतू अपने तीनों बच्चों के साथ खून से लथपथ मृत पड़ी थी। वहीं, राजेंद्र घर से गायब था। प्रथम दृष्टया यह बात सामने आई है कि राजेंद्र किसी तांत्रिक के संपर्क में था। तांत्रिक का कहना था कि उसकी प्रगति की राह में उसकी पत्नी और बच्चे बाधक हैं। इसी वजह से राजेंद्र ने पत्नी और बच्चों की हत्या की है। पुलिस राजेंद्र के साथ ही तांत्रिक की भी तलाश शुरू कर दी है। राजेंद्र हत्या के मामलों में पहले भी जेल में रह चुका है। उसके मकान में तकरीबन 20 किरायेदार रहते हैं। वह देसी शराब ठेका का संचालक भी है। दूसरी तरफ, पुलिस और जानकारी इकट्ठा करने के लिए पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। आसपास के लोगों ने बताया कि 20 वर्ष पहले भी आरोपी राजेंद्र गार्ड के साथ कई हत्याएं कर चुका है। वह जेल में सजा काटकर आया है। यह उसकी दूसरी पत्नी थी। वहीं, मौके पर पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल भी पहुंच गए। पूछताछ के साथ ही भेलूपुर पुलिस आरोपी राजेंद्र गुप्ता का और इतिहास खंगाल रही है। यह भी पता किया जा रहा है कि वह तांत्रिक कौन था जिससे राजेंद्र मिलता–जुलता था। उधर, पत्नी और तीन बच्चों की हत्या के आरोपी राजेंद्र गुप्ता का शव रोहनिया थाना क्षेत्र के एक गांव में मिलने की सूचना मिलने लगी। खबर लिखे जाने तक पुलिस मौके पर पड़ताल करने पहुंची थी।

लाठी व ईंट से पीट कर रिटायर्ड सिपाही की हत्या

आजमगढ, संवाददाता। आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के जमीन हरखोरी (लड़ीहा) गांव में नाली के विवाद को लेकर बीती रात पटीदारों ने रिटायर्ड सिपाही की लाठी–डंडे से पीटकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपियों की तलाश में पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। जमीन हरखोरी गांव के पुरवा लड़िया निवासी रिटायर्ड सिपाही नरसिंह यादव (65) सोमवार की सुबह घर के सामने नाली की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान घर के बगल में रहने वाले पटीदार बलजीत यादव से उनकी कहासुनी हो गई। इसके बाद कुछ लोगों ने बीच में पड़कर मामले को रफा–दफा कर दिया। इसके बाद बीती रात करीब 9:30 बजे के करीब बालजीत और उनके बेटों ने मिलकर रिटायर्ड सिपाही नरसिंह को लाठी–डंडे से पीटकर घायल कर दिया। घायल नरसिंह को लेकर परिजन एक निजी अस्पताल पहुंचे और उन्हें भर्ती कराया। इलाज के दौरान नरसिंह यादव की मौत हो गई।

173 कन्फर्म सीटें यात्रियों को हुईं नसीब... अब वापसी की यात्रा आसान

लखनऊ, संवाददाता। दीपावली के बाद लोगों का काम पर वापसी का दौर जारी है। दिल्ली, मुंबई, हावड़ा रूट की ट्रेनों में वेटिंग बनी हुई है। अगले हफ्ते से राहत मिलने की उम्मीद अफसर जता रहे हैं। खास बात यह है कि सोमवार को तत्काल कोटे से यात्रियों को राहत मिली। 489 सीटों में 173 कन्फर्म सीटें यात्रियों को नसीब हुईं। जबकि पिछले एक हफ्ते से यात्रियों को मायूसी हाथ लग रही थी। मंगलवार को लखनऊ से दिल्ली, मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़, देहरादून, पटना आदि जगहों पर जाने के लिए कन्फर्म ट्रेन टिकट की आस में पैसेंजर आरक्षण केंद्रों पर सोमवार को जुटे। दरअसल, तत्काल कोटे के टिकट की बुकिंग यात्रा के एक दिन पहले होती है। पिछले एक हफ्ते से जहां यात्रियों को तत्काल कोटे से यात्रियों को मायूसी हाथ लग रही थी।

तत्काल कोटे की 173 कन्फर्म सीटें यात्रियों को मिलीं

वहीं सोमवार को यात्रियों को मामूली राहत मिली। उपरोक्त रूटों पर चलने लखनऊ मेल, एसी एक्सप्रेस, गोरखधाम, कैफियत, पुष्पक, कुशीनगर, गोरखपुर एलटीटी, लखनऊ चंडीगढ़, दून एक्सप्रेस, पटना कोटा एक्सप्रेस आदि ट्रेनों में 489 सीटें तत्काल कोटे की रहीं। इन पर यात्रियों ने बुकिंग करवाई। एसी व स्लीपर श्रेणी में तत्काल कोटे की 173 कन्फर्म सीटें यात्रियों को मिलीं।

इन ट्रेनों में सीट मिलने की अफसर जता रहे उम्मीद

लखनऊ से दिल्ली व मुंबई जाने वाली नियमित ट्रेनों में कन्फर्म टिकटों की जद्दोजहद इस हफ्ते और रहेगी। अगले हफ्ते से कुछ राहत मिल सकती है।

मुंबई जाने वाली स्पेशल ट्रेनों व दिल्ली रूट की चेयरकार ट्रेनों वंदे भारत, तेजस, शताब्दी आदि ट्रेनों में यात्रियों को कन्फर्म सीटें मिलने की उम्मीद अफसर जता रहे हैं।

डीजीपी की नियुक्ति के निर्णय पर अखिलेश ने कसा तंज, दिल्ली से अपने हाथ में लगाम लेने की कोशिश

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश में सोमवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसी में डीजीपी की नियुक्ति पर भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। इसके बाद यूपी में डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार के स्तर से ही हो सकेगी। इस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा है। कहा कि कहीं दिल्ली से अपने हाथ में लगाम लेने की कोशिश तो नहीं है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि, सुना है, किसी बड़े अधिकारी को स्थाई पद देने और उसका कार्यकाल दो वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। अब सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद दो वर्ष रहेंगे या नहीं ? इसके बाद उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है? दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0। कैबिनेट बैठक में इसे दी गई थी मंजूरी

प्रदेश में अब डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार के स्तर से ही हो सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट ने इस बाबत पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश के पुलिस बल प्रमुख) चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी। इसमें हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में मनोनयन समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है। वहीं डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष निर्धारित किया गया है। मनोनयन समिति में मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित अधिकारी, उप्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या नामित अधिकारी, अपर मुख्य सचिव गृह, बतौर डीजीपी कार्य कर चुके एक सेवानिवृत्त डीजीपी सदस्य होंगे। इस नियमावली का उद्देश्य डीजीपी के पद पर उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति के चयन के लिए स्वतंत्र एवं पारदर्शी तंत्र स्थापित करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसका चयन राजनीतिक या कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त है।

मनोनयन समिति करेगी विचार

साथ ही प्रदेश की विशिष्ट दशाओं तथा पुलिसिंग आवश्कताओं के अनुरूप भी है। डीजीपी का चयन राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए उनकी सेवा अवधि, सामान्यतरू बहुत अच्छे सेवा रिकॉर्ड और अनुभव की सीमा के आधार पर किया जाना प्राविधानित किया गया है। मनोनयन समिति उन अधिकारियों के नाम पर विचार करेगी, जिनकी सेवानिवृत्ति में छह माह से अधिक शेष है। केवल उन नामों पर ही विचार किया जाएगा, जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 16 में डीजीपी के पद पर कार्यरत हैं। डीजीपी को पद से हटाने से संबंधित प्राविधानों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित दिशा–निर्देशों का पालन किया गया है।

मायावती ने मदरसा शिक्षा बोर्ड के फैसले का किया स्वागत

लखनऊ, संवाददाता। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून–2004 को वैध व संवैधानिक करार दिए जाने के फैसले

बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला स्वागतयोग्य है। उन्होंने उम्मीद जताई की इस निर्णय से अब मदरसा शिक्षा को लेकर उपजे विवाद व हजारों मदरसों की अनिश्चितता समाप्त हो जाएगी। सोशल साइट एक्स पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज एक अहम फैसले में यूपी मदरसा शिक्षा का स्वागत है। इससे यूपी में मदरसा शिक्षा को लेकर उपजे विवाद व हजारों मदरसों की अनिश्चितता अब निश्चय ही समाप्त होने की संभावना है। इस पर सही से अमल जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब खासकर यूपी के मदरसों को मान्यता मिलने और उनके सुचारू संचालन में स्थायित्व आने की संभावना है। अदालत ने कहा कि मदरसा एक्ट के प्रावधान संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं और ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट की 9–जजों की बेंच द्वारा हर निजी सम्पत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत सामुदायिक सम्पत्ति का हिस्सा नहीं मानना व इसका अधिग्रहण करने से रोकने के फैसले का भी स्वागत योग्य है। अब तक सरकार के पास आम भलाई हेतु सभी निजी सम्पत्तियों को अधिगृहित करने का अधिकार था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। कोर्ट ने कहा कि यह धर्म निरपक्षेता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था देकर गलती की कि मूल ढांचे यानी धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के कारण उत्तर प्रदेश मदरसा कानून को खारिज करना होगा।

लखनऊ में मिला कालाजार का मरीज

लखनऊ, संवाददाता। अभी तक नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में मिलने वाली बीमारी कालाजार अब राजधानी लखनऊ पहुंच गई है। यहां एक मरीज में इसकी पुष्टि हुई है। खास बात यह है कि इस मरीज की कोई यात्रा इतिहास भी नहीं है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की टीम ने भी मौका मुआयना किया। जिस घर में मरीज मिला है, उसके आसपास रहने वाले 500 परिवारों की जांच कराने की तैयारी है। प्रदेश में प्रति 10 हजार की आबादी पर 0.5 केस होने की वजह से वर्ष 2019 में कालाजार बीमारी को खत्म मान लिया गया। डब्ल्यूएचओ के मानक के अनुसार एक ब्लॉक में एक हजार की आबादी पर प्रति वर्ष एक मरीज मिलता है तो इसे उन्मूलन की श्रेणी में मान लिया जाता है। अभी तक प्रदेश में मानक से कम मरीज मिल रहे हैं। वर्ष 2024 में अब तक देवरिया में एक, कुशीनगर में सात और बलिया में दो मरीज मिले हैं। इनकी निगरानी चल रही है। इसी बीच सप्ताहभर पहले राजधानी लखनऊ के त्रिवेणी नगर में 17 साल के युवक में कालाजार की पुष्टि हुई है। युवक एक निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती था। डेंगू, मलेरिया सहित सभी तरह की जांच कराई गई। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी बुखार बना रहा। लक्षण के आधार पर कराई गई जांच में कालाजार की पुष्टि हुई। कॉलेज प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी। आनन– फानन में डब्ल्यूएचओ और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौका मुआयना किया। इस केस के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। क्योंकि अभी तक लखनऊ में कालाजार का कभी कोई केस नहीं मिला है। इतना ही नहीं युवक का कोई यात्रा इतिहास भी नहीं है। युवक से कोई पूर्वांचल से मिलने भी नहीं आया है। ऐसे में विभाग ने मरीज के घर में जांच कराई, जहां कालाजार फैलाने वाली बालू मक्खी पाई गई है। संयुक्त निदेशक (कालाजार) डा. एके चौधरी बताया कि बालू मक्खी के मिलने के कारणों की भी जांच कराई जा रही है। संभव है कि यह जानवरों के जरिए यहां पहुंची हो। संयुक्त निदेशक (कालाजार) डा. एके चौधरी ने बताया कि विभागीय टीम पूरी तरह से अलर्ट है। अब मरीज की हर 15 दिन में निगरानी की जाएगी। जिला मलेरिया अधिकारी को निर्देश दिया गया कि मरीज के घर के साथ ही आसपास के 500 परिवारों के घरों में सिंथेटिक पायरेथ्रायड का खिड़काव किया जाएगा। इसके बाद इन घरों में बुखार का कोई भी केस आएगा तो उनकी जांच कराई जाएगी। इसके लिए किट भी मंगाई जा रही है। आमतौर पर लखनऊ में कालाजार के मरीज नहीं मिलते रहे हैं। मरीज में बीमारी की पुष्टि होने के बाद बचाव के सभी उपाय शुरू कर दिए गए हैं। अन्य जिलों को भी अलर्ट किया गया है। जहां पहले से मरीज मिलते रहे हैं, उन जिलों में खासतौर से निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

घाटों-अपार्टमेंट में हुई पूजा की तैयारियां, छेड़खानी रोकने के लिए सक्रिय रहेंगे एंटी रोमियो स्क्वायड

लखनऊ, संवाददाता। संतान की समृद्धि, खुशहाली व अच्छी सेहत के लिए रखे जाने वाले छठ महापर्व का शुभारंभ मंगलवार भोर से हो रहा है। इसके मद्देनजर सोमवार को घाटों पर श्रद्धालु सुशोभिता बनाते नजर आए। घरों व अपार्टमेंट में भी छठ माई की पूजा के लिए विशेष सफाई की गई। स्नान के लिए अपार्टमेंट व आवासीय समितियों में भी अस्थायी कुंड बनाए गए हैं। छठ पूजा प्रकृति को समर्पित पर्व है जिसमें सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा होती है। यह पर्व चार दिन चलता है जिसका आरंभ चतुर्थी तिथि से हो जाता है और समापन सप्तमी तिथि पर होता है। छठ पर्व पर व्रती कमर तक जल में प्रवेश कर सूर्यदेव को अर्घ्य देती हैं। छठ की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है। इस त्योहार का समापन सप्तमी पर होता है। यह महापर्व पांच से आठ नवंबर तक मनाया जाएगा। कुड़ियाघाट, लक्ष्मण मेला घाट, पंचवती घाट और गऊघाट पर सोमवार देर शाम तक तैयारियां होती रहीं।

खरना कल, छठ मैया को लगेगा गुड़ की खीर का भोग

आचार्य एसएस नागपाल के मुताबिक, छठ पर्व मुख्य रूप से षष्ठी तिथि को किया जाता है। इसका आरंभ नहाय खाय से पांच नवंबर से हो रहा है। पहले दिन व्रती महिलाएं नदियों में स्नान कर कद्दू की सब्जी, लौकी, भात, सरसों का साग एक समय खाती हैं। दूसरे दिन छह नवंबर को खरना या लोहंडा किया जाएगा। इसमें शाम के समय व्रती महिलाएं गुड़ की खीर बनाकर छठ मैया को भोग लगाती हैं। पूरा परिवार इस प्रसाद को खाता है। तीसरे दिन सात नवंबर को छठ महापर्व मनाया जाएगा जिसमें अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन सप्तमी तिथि पर आठ नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व का समापन होगा। छठ पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, चावल के लड्डू, फलों और नारियल का प्रयोग किया जाता है।

इसलिए देते हैं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य

छठ पूजा में तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है, क्योंकि यह समय प्रतीकात्मक रूप से जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों को समाप्त करने और नवजीवन का आरंभ करने का संकेत देता है। डूबते सूर्य की पूजा करके व्यक्ति नई ऊर्जा के साथ अगली सुबह का स्वागत करने की शक्ति प्राप्त करता है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने छठ पर्व के दौरान छेड़खानी की घटनाओं की रोकथाम के लिए एंटी रोमियो स्क्वायड को सक्रिय रखने और सादे कपड़ों में महिला व पुरुष पुलिसकर्मियों को तैनात करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सोमवार को इस बाबत सभी पुलिस कमिश्नर, एडीजी जोन, आईजी रेंज और जिलों के कप्तानों को रेलवे स्टेशनों व बस अड्डों पर भी पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने को कहा। डीजीपी ने कहा कि छठ पर्व के अवसर पर घाटों, पूजा स्थलों, नदियों व तालाबों आदि पर महिलाओं के अतिरिक्त बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं. इनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए। इन जगहों पर प्रकाश, साफ–सफाई और गोताखोरों की समुचित व्यवस्था भी की जाए। प्रमुख घाटों पर अग्निशमन वाहनों को भी तैनात किया जाए। वहीं ट्रेनों व बसों से बड़ी संख्या में लोगों के आवागमन के मद्देनजर कार्ययोजना तैयार कर ली जाए। फुट पेट्रोलिंग के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया जाए। स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारियों व कर्मचारियों को सतर्क रखने के साथ ही असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए।

अखिलेश यादव हार के भय से कुछ भी आंये... बांये... सांये बोल

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश में इन दिनों उपचुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। इसके साथ ही पोस्टर वार भी जारी है। सियासी बयानबाजी के क्रम में अब योगी के मंत्री धर्मपाल सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश को भय है कि उपचुनाव की सभी नौ सीटों पर सपा की जमानत न जब्त हो जाए, इसलिए कुछ भी आंये... बांये... सांये बोल रहे हैं।

उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री धर्मपाल सिंह ने अमर उजाला से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए प्रदेश में तीन फैक्ट्रियां लगाने को मंजूरी मिली है। ये फैक्ट्रियां कानपुर, कन्नौज और गोरखपुर जिलों में लगाई जाएंगी। इसमें प्रतिदिन करीब छह लाख लीटर दूध खरीदा जाएगा। इससे किसानों को काफी लाभ होगा। उन्होंने इसका भुगतान भी समय पर दिएया जाएगा।

एक हफ्ते बढ़ी मतदान की तारीख

इसके बाद उन्होंने उपचुनाव को लेकर बातचीत की। प्रदेश की नौं सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख को एक हफ्ते बढ़ा दिया गया है। इस सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा था।

उन्होंने अक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि हार के भय से ये भाजपा की पुरानी चाल है। श्टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे!श

सपा की जमानत जब्त होगी

इस पर मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को हार का डर है। वह कुछ भी आंये... बांये... सांये बोल रहे हैं। उनको लगता है कि सभी सीटों पर सपा की जमानत न दर्ज हो, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं।

खतरनाक हुई राजधानी की हवा, 433 पहुंचा वायु गुणवत्ता सूचकांक

लखनऊ, संवाददाता। दीपावली के बाद राजधानी की हवा खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। तालकटोरा क्षेत्र में सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक स्तर 433 तक पहुंच गया। इस साल में किसी भी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक का यह सबसे खराब स्तर है। इससे पहले दिवाली की रात अलीगंज क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 तक ही पहुंचा था। तालकटोरा क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक स्तर की यह स्थिति तब जब है जब पिछले कई दिन से क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयां बंद थीं। दीपावली की रात भी तालकटोरा क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 378 तक ही पहुंचा था। आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर और खराब होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि तालकटोरा के अलावा अन्य क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक उतना खराब नहीं रहा। गोमतीनगर क्षेत्र में यह स्तर 136 के साथ पीले श्रेणी में रहा। अलीगंज में 342 (लाल), लालबाग में 271 (नारंगी), कुकरैल में 203 (नारंगी) और बीबीएयू क्षेत्र में 226 (नारंगी) रहा।

दो डिग्री तक बढ़ गया रात का तापमान

शहर की खराब होती हवा के बीच ही तापमान में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। रात का तापमान दो डिग्री बढ़कर अब 18.3 सेल्सियस पहुंच गया है। वहीं दिन का तापमान अभी भी 32.7 डिग्री के स्तर पर बना हुआ है।

महाकुंभ में सब को छूट है, संतों ने की गैर हिंदुओं के आने पर रोक लगाने की मांग

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के अमेठी में मंगलवार को मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद पहुंचे। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें डीएम निशा अनंत, एसपी अनूप सिंह और भाजपा के जिलाध्यक्ष राम प्रसाद मिश्र समेत मत्स्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। कहा कि सरकार आधुनिक तरीके से मत्स्य पालन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। इससे मछली पालकों को भी बड़ा फायदा होगा। बड़े–बड़े तालाबों और पोखरों को मत्स्य पालन के लिए उपयोग किया जाएगा।

महाकुंभ में सभी धर्म के लोगों को आने की छूट

हाल ही में संतों ने प्रयागराज महाकुंभ में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। इस सवाल पर संजय निषाद ने कहा कि सभी धर्म के लोगों ने मिलकर सरकार बनाई है। सरकार बिना भेदभाव के सबके लिए काम कर रही है। प्रयागराज महाकुंभ में सभी धर्म के लोगों को आने की छूट है।

कटेंगे तो बटेंगे पर भी दिया बयान

उपचुनाव को देखते हुए सीएम योगी के कटेंगे तो बटेंगे बयान पर कहा कि यह सही बात है। पिछली सरकारों में हिंदू–मुसलमान राइट होता था। लेकिन, अब शांति हो गई है। राष्ट्र के नाम पर सभी एक हो गए हैं।

संक्षिप्त खबरें

सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी पर मुकदमा

लखनऊ, संवाददाता। युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी पर कृष्णानगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपी को कोर्ट फरार घोषित कर चुकी है। आजमगढ़ के निजामाबाद में रहने वाले अंगद ने 23 जुलाई को साथी अमन यादव के साथ मिलकर युवती से दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी अमन को 21 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि अंगद की तलाश जारी थी। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए उसके घर पर भी दबिश दी थी। कोर्ट ने 17 सितंबर को अंगद को फरार घोषित किया था। समन तामील होने के बाद भी अंगद कोर्ट में पेश नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर कृष्णानगर पीके सिंह के मुताबिक आरोपी की तलाश चल रही है।

नौकरी के नाम पर सिविल इंजीनियर से 3.50 लाख ठगे

लखनऊ, संवाददाता। बरेली के प्रेमनगर में रहने वाले सिविल इंजीनियर अमान नवाज ने फर्म संचालक समेत सात लोगों पर साढ़े तीन लाख की ठगी की रिपोर्ट विकासनगर थाने में दर्ज कराई है। आरोपियों ने एनसीईआरटी में सर्वेयर की नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। अमान नवाज एक निर्माण फर्म में काम करते हैं। फर्म में उनकी मुलाकात विकासनगर स्थित मामा चौराहे के पास श्रद्धा इंटरप्राइजेज फर्म के मालिक आलोक पांडेय से हुई। आलोक ने एनसीईआरटी में सर्वेयर की नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। हामी भरने पर उनकी मुलाकात चंद्रशेखर, पवन, अजय, सर्वेश, प्रदीप और कृष्णकांत से कराई थी। रकम के भुगतान पर आरोपियों ने नियुक्ति पत्र भी दे दिया। अमान ने कुछ माह तक स्कूलों में जाकर सर्वे भी किया। पर वेतन नहीं मिला। जांच करने पर पता चला कि उनकी नौकरी लगी ही नहीं है। नियुक्ति पत्र भी फर्जी था।

महिला ने पिल्ले को डंडे से पीटा, दोनों पैर टूटे

लखनऊ, संवाददाता। महिला की पिटाई से पिल्ले के दो पैर टूट गए। विरोध पर आरोपी ने पिल्ले का इलाज कराने की बात कही, पर बाद में मुकर गई। पड़ोसी ने पारा थाने में केस दर्ज कराया है। पारा के सूर्यनगर में रहने वाली अस्मिता बरला के मुताबिक 13 अक्तूबर को पड़ोसी निशी के घर पास एक माह का पिल्ला टहल रहा था। निशी की मां ने डंडे व तार से उसे पीट दिया। अस्मिता जब पिल्ले को बचाकर अस्पताल ले गईं तो पता चला कि उसकी पीछे के दोनों पैर टूट गए। इस कारण वह चल नहीं सकेगा। इलाज कराकर वह पुलिस के साथ आरोपी महिला के घर पहुंचीं। उसने इलाज कराने की बात कही, पर बाद में मुकर गईं। एडिश्नल इंस्पेक्टर के मुताबिक पशु क्रूरता अधिनियम की धारा में केस दर्ज किया गया है।

राजकीय कालेज की छात्राओं के लिए कथक प्रशिक्षण शुरू

लखनऊ, संवाददाता। राजकीय हाईस्कूल मस्तेमऊ गोसाईंगंज में नई शिक्षा नीति के तहत छात्राओं के व्यक्तित्व विकास को लेकर उनके लिए कथक का प्रशिक्षण शुरू हुआ है। मंगलवार को इसकी शुरुआत बिरजू महाराज कथक संस्थान की अध्यक्ष डॉ. कुमकुम धर के नेतृत्व में हुई। प्रशिक्षिका अदिति थपलियाल ने छात्राओं को कथक की बारीकियों के बारे में बताया। अदिति ने बताया कि यह कला मात्र कथक नृत्य के विषय में ही नहीं है अपितु हमारी जड़ों से जुड़ने, आत्मविश्वास बढ़ाने और छात्र–छात्राओं में आत्मविश्वास व रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रेरित करने का प्रयास है।

नकदी व रिक्शा चोरी कर भाग रहे युवक को पकड़ा

लखनऊ, संवाददाता। माधवखेड़ा गांव में सोमवार को चौकीदार ने नकदी व रिक्शा चोरी कर भाग रहे युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर आलोक राव के मुताबिक गांव निवासी नवल किशोर का श्री दुर्गा ट्रेडर्स नामक दफ्तर है। सोमवार रात करीब दो बजे बहराइच के महाराजगंज का रहने वाला मोहन नवल के दफ्तर में घुस गया और गल्ले में रखे दो हजार रुपये, दो मोबाइल व रिक्शा लेकर भागने लगा। खटपट की आवाज आने पर उठे चौकीदार दीपू ने आरोपी को पकड़ लिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी को जेल भेजा गया है।

शूटिंग के बहाने डाक्टर का घर कब्जाने की कोशिश

लखनऊ, संवाददाता। इंदिरानगर इलाके में रहने वाले एक डॉक्टर का घर शूटिंग पर लेकर कब्जा करने का प्रयास किया गया। डॉक्टर की पत्नी का आरोप है कि मकान पर कब्जा करवाने के लिए 40 से 50 वकील पहुंचे थे। वकीलों को इतनी बड़ी संख्या में साथ में देखकर पीड़िता घबरा गईं। उन्होंने मदद के लिए 112 को कॉल की। पुलिस ने हस्तक्षेप करके वकीलों को वहां से हटाने के साथ धार्मिक कार्यक्रम बंद करवा दिया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पक्ष के लोगों ने उनके घर के एक हिस्से में बाहर से ताला लगा दिया है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 - 7007415808, 9628325542, 9415034002
RNI NO - UPHIN/2022/86937
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।